(a) Consequent upon the decision taken in a meeting on 24th July, 1991, presided by the Minister for Public Works of Arunachal Pradesh, the State, Governments has decided to implement the Nehru Roz-gar Yojana.

(b) Amount of Rs. 28.72 Lakhs and Rs. 25.46 lakhs were released by the Go-verrment of India to the State Government for the Years 1989-90 and 1990-91 respectively. The tentative allocations under the scheme for Arunachal Pradesh during the current year is Rs. 25.46 lakhs.

(c) The State Government has not reported any utilization of funds so far.

Seminar on landscaping and kitchen gardening

887. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to State;

(a) whether a seminar on modern trends in ladscaping and kitchen gardening has been organised at New Delhi by All India Kitchen Garden Association recently;

(b) whether the seminar was attended by a large number of participants;

(c) if so. what are the names of States represented in the stminar nnd the issues discussed there;

(d) whether Government propose to extend some assistance to AH India Kitchen Garden Association to encourage kitcher gardesihg and landscaping; and

(e) if so, the details thereof and if not. the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNAGKALAM): (a) The Seminar is scheduled to be held on 28th November, 1991.

(b) and (c) Do not arise.

(d) and (e) Financial assistalce of Rs. 10.000/- has been sanctioned under the scheme 'Assistance to Professional Societies/Organisations for the promotion of horticulture activities to the Association by the Ministry of Agriculture.

जवाहर रोजगार योजना

888. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में भी जवाहर रोजगार योजना जैसी ही कोई योजना आरंभ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) योजना के ब्यौरे विवरण I में दिये गये हैं । **(नीचे देखिये)**

(ग) योजना के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान नियतन के लिये प्रस्तावित राशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण II में दिये गये हैं ।

विवरण I

नेहरू रोजगार योजना

बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार शहरी निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 1989 में नेहरू रोजगार योजना आरंभ की गई थी। यह योजना शहरी मलिन बस्तियों में गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन बिताने वाले परिवारों पर लागू है तथा इस व्यापक श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं का एक विशेष लक्ष्य समूह है ।

(i) शहरी लघु उद्यम योजना (एस० यू०एम०ई०) का उद्देश्य कौशल का उन्नयन तथा आर्थिक सहायता और उद्योग, सेवाएं तथा कारोबार के क्षेत्र में लघु उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से शहरी निर्धन लाभ भोगियों के लिए ऋण की व्यवस्था करना है । शहरी लघु उद्यम योजना, सभी शहरी बस्तियों पर लागू है । प्रशिक्षण घटक पर सम्पूर्ण व्यय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है । आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले व्यय को केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है ।

(ii) शहरी मजदूरी रोजगार योजना (एस० यू० डब्ल्यू० ई०) का उद्देश्य एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आर्थिक तथा सामाजिक उपयोग के सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण करने के माध्यम से शहरी निर्धन लाभभोगियों के लिए मजदूरी श्रम की व्यवस्था करना है । सामग्री श्रम का अनुपात 60 : 40 का है । इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 80:20 के आधार पर बांटा जाता है ।

(iii) आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना (एस० एच० ए० एस० यू०) का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर लाभ भोगियों के रिहायसी यूनिटों का उन्नयन करने के लिए निर्माण व्यापार में प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ 4000/- रुपए की अधिकतम सीमा का (आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा रुपए 1000/- तथा ऋण की अधिकतम सीमा रु० 3000/-) हुडको से ऋण तथा आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना है ।

आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) की आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों का भी लाभ उठाया जा सकता है । यह योजना एक लाख तथा 20 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होती है । पर्वतीय राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों अथवा पहाड़ जिलों (योजना आयोग द्वारा यथा परिभाषित) तथा नए औद्योगिक नगर-क्षेत्र में स्थित 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों को छूट दी गई है । प्रशिक्षण घटक का संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 80:20 के अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है ।

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना-1991-92 लिये केन्द्रीय निधियों का नियतन

(रु० लाखों

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों अवन्तिम नियतन
1.	आन्ध्र प्रदेश	851.
2.	बिहार	878.
3.	गुजरात	408.
4.	हरियाणा	155.
5.	कर्नाटक	842.
6.	केरल	345.
7.	मध्य प्रदेश	864.
8.	महाराष्ट्र	994.
9.	उड़ीसा	294.
10.	पंजाब	287.
11.	राजस्थान	568.
12.	तमिलनाडु	918
13.	उत्तर प्रदेश	2257.
14.	पश्चिम बंगाल	707.
15.	गोवा	29.
16.	अरुणाचल प्रदेश	34
17.	आसाम	174
18.	हिमाचल प्रदेश	66
19.	जम्मू और कश्मीर	93
20.	मणिपुर	42
21.	मेघालय	39

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधियों का अनन्तिम नियतन
22.	मिजोरम	26.12
23.	नागालैण्ड	41.47
24.	सिक्किम	30.20
25.	त्रिपुरा	25.83
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	12.53
27.	चण्डीगढ़	23.65
28.	दादर तथा नागर हवेली	11.45
29.	दमन तथा दीव	20.03
30.	पांडिचेरी	29.75
31.	दिल्ली	3.50
	योग :	11080.00

Increase In the price of flats in Delhi Development Authority

889. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT iJHANDARE; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Hindustan Times of 3rd October, 1991 under the caption "DDA shocks' MIG allottees";

(h) if 'so, what was the original estimated cost of the MIG flats constructed in Jahangirpuri, Delhi under the 1979 scheme; and by what time they were scheduled to be completed;

(c) what is the extent of delay in constructing the flats and the escalation caused thereby; and

(d) what are the details of the protests lodged by the allottees of these flats?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM)-(a) Yes, Sir.

(b) No specific estimated cost for flat* in Jahangirpuri was announced at the time of registration under New Pattern Scheme, 1979. Howeper, for MIG category of flats the cost was estimated at Rs. 42,000/- which was subjest to revision/ modification.

fc) In February 1991, 224 MIG flats were released for allotment in Jahangirpuri. The extent of delay in construction of these flats is almost 8 years. The costing of flats is done on the basis of actual expenditure incurred on the project.

(dl The complaint referred to in the News item has been brought to the no-t'ce of she DDA.

Urban rent control act

890. SHRI BEKAL UTSAHI; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether it is a fact that urban rent control and tenancy Acts, as at present, are in favour of the tenants against the house-owners thus resulting in a high per" centage of housing units remaining va cant and unused;

(b) whether Government are contem plating any exercise toward rationalisation cr these laws for Metropolitan cities.

(c) whjthsr Gopernment have conducted any survey on the extent of vacant -*i*welling units in each of the metropolitan cities; if so, what are the details Hereof?

THE MNIISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The Government is aware of the adverse effect of rent control legislation on the increased supply of rental housing. Rent control is a State Subject and states are fully competant to enact suitable legislation to control various aspects of rental housing. However, the Central Government is formulating a modal Rent Control Bill for adoption by different States with appropriate change* to suit local conditions.

(c) No, Sir.